ORIGINAL RESEARCH PAPER

Economics

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की सार्थकता: बिहार के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन

KEY WORDS:

डॉ.अनामिका कुमारी विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर दरभंगा।

ABSTRACT

बिहार भारत का एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, जो भूख और कुपोषण से ग्रसित है। अगर हमें बिहार से भुखमरी और कुपोषण को जड़ से खत्म करना है।तो इसके लिए हमें सामाजिक,आर्थिक और पारंपरिक स्तर पर भुखमरी और कुपोषण को जड़ से मिटाना होगा, जिसके लिए हमें सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने पर बल देना होगा। इसके लिए हमें सरकारी नीतियों के अलावा जनता में भी जागरूकता लाने का प्रयास करना होगा। जिससे कुपोषण एवं भुखमरी से निदान मिल सके एवं खाद्य सुरक्षा में पोषण की सार्थकता सिद्ध हो सके। इसके लिए हमें हर स्तर पर खुद ही नए कदम उठाने होंगे।

परिचय :

कुपोषण और भुखमरी के मामले में बिहार की बेहद दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहां जनसंख्या की अधिकता है, एवं संबंधित संसाधनों की कमी है, जिसके कारण बिहार में कुपोषण के मामले अधिक है।सरकारी प्रयासों के तहत इस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका है, लेकिन अभी भी यह संतोषजनक स्थिति नहीं है। कुपोषण को आज मानव विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्व माना गया है। यह साधारणतःबचपन से ही शुरु होता है, और अपने अल्प, मध्यमऔर दीर्घ परिणामों से जीवन भर स्वस्थ समझने का सामर्थ्य ,उत्पादकता और उत्तरजीविता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। चुंकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदाय वर्गों पर कुपोषण का असर ज्यादा आसानी से पड़ता है। कुपोषण से सामाजिक और समानताएं बढ़ती है।

बिहार में कुपोषण की वर्तमान स्थिति :

बिहार में अल्प पोषण की दरें अनेक प्रकार से राष्ट्रीय औसत से बढ़ी है। बिहार की जनसंख्या देश की आवादी की लगभग **9%** है। इस प्रकार बिहार राष्ट्रीय वस्तुओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। बिहार में वर्ष **2006** एवं **2015** के बीच अल्प पोषण में सकारात्मक लेकिन सीमित परिवर्तन देखा गया है।नाटापन में **56** प्रतिशत से **48** प्रतिशत, दुबलापन में **27** प्रतिशत से **21** प्रतिशत तक गिरावट आई है। **(NFHS 3-4)** गंभीर दुबलापन **8. 3** प्रतिशत से घटकर **7** प्रतिशत हुई है।

(ये आंकड़ा **:-** बिहार में वर्ष **2006-2015** का है।**)**

बिहार में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की उपलब्धता :

बिहार में खाद सुरक्षा से पोषण सुरक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। पोषण सुरक्षा में संतुलित आहार, स्वच्छ जल ,स्वच्छता व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं शारीरिक ,आर्थिक और सामाजिक होना चाहिए। इसके अलावा पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से औषधि से अधिक स्वच्छ खाद्य सामग्री आवश्यक है। पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में खाद पर्याप्ता, प्रोटीन की कमी व आयरन ,आयोडिन,जिंक विटामिन ए आदि की कमी की तरफ भी ध्यान देना अति आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा से पोषण के विभिन्न लक्ष्यों की प्राथमिकताएं :

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहां **71.10%** जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। खाधान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं खाद्यान्न की कमी को दूर करने में कृषि की अहम भूमिका है, लेकिन वर्तमान में कृषि क्षेत्र में राहत कार्यक्रमों को कम किया जा रहा है। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसा ना हो एवं जिन फसलों में हमें पोषण प्राप्त नहीं होता उनका उत्पादन कम कर के पोषण प्रदान करने वाले फसलों का उत्पादन करना चाहिए। कृषि और पोषण नीति के बीच आपसी तालमेल आवश्यक है, जिससे उपभोग के लिए पोषण पूर्ण स्थानीय फसलों के उत्पादन को बढ़ावा एवं सहयोग देने की आवश्यकता है।जैसे पोषक तत्वों से युक्त मखाना एवं सहजन की खेती बिहार में काफी प्रचलित है। मखाना एक पोषक तत्वों से भरपूर जलीय उत्पाद है, और सहजन बहुत ही उपयोगी पौधा है।जो बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर है एवं काफी पोषण प्रदान करता हैबिहार में खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सहजन की खेती भी बहुत महत्वपूर्ण है। सहजन के सभी भागों का प्रयोग भोजन ,दवा, एवं औद्योगिक का कार्य आदि के लिए किया जाता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में **4** गुना पोटैशियम तथा संतरा की तुलना में **7** गुणा विटामिन है। सिर्फ आवश्यकता है ध्यान देने की, जिससे कि कुपोषण से निपटा जा सके। इसके लिए स्थानीय फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होना चाहिए।

समाज कल्याण विभाग के तहत कार्य समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में पोषण अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रमुख कार्य निम्न है :

- कुपोषण के विरुद्ध जन जागरूकता का प्रसार करना।
- **6** वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर को वर्तमान **34.8** किसी से कम करके **2022** तक **25** फ़ीसदी पर लाना।
- प्रत्येक माह पोषण कैलेंडर के अनुसार पोषण गतिविधियां संचालित करना।
- बच्चों ,किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए शिविर का आयोजन करना।
- पोषण के लिए अनुपूरक आहार वितरण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों का संचालन।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की समुदाय आधारित जानकारी प्रदान करना।
- पोषण प्रदान करने वाले स्थानीय फसलों का भरपूर मात्रा में उत्पादन करना।

इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के अंतर्गत निम्न घटकों को भी सम्मिलित होना चाह।

(1) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी उपयोग व अभिवर्धित फूड बास्केट जिसमें चावल व गेहूं के साथ बाजरा भी शामिल है के उपयोग से कुपोषण को दूर करना।

(2) दाल,उत्पादन एवं दूध व मुर्गी उत्पादन के जरिए प्रोटीन उपयोग को बढ़ाना।

(3) बेहतर फसल प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले खाद्य गुणवत्ता व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

इसके अतिरिक्त मिशन में साफ पेयजल स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व पोषण साक्षरता के प्रावधान भी सम्मिलित होना चाहिए।

निष्कर्ष :

सतत विकास के लिए देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्याप्त मात्रा में भोजन या जरूरी पोषण नहीं मिलने से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। भोजन की उपलब्धता में क्षेत्रीय स्तर पर और असमानता रहने और खानपान की अलग-अलग आदतों के कारण भी कुपोषण

की समस्याएं उत्पन्न होती है। यह शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज्यादा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम निवेश और बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम काफी कारगर सिद्ध होंगे।

संदर्भ - स्त्रोत

(1) स्वामीनाथन एम.एस व एस.के. सिन्हा, (1985) ग्लोबल स्पेक्ट्रम ऑफ फूट प्रोडक्शन टिकुली इंटरनेशनल पब्लिशिंग, कंपनी डब्लिन।

(2) शमिका रवि ,योजना, मई (2018)।

(3) बिहार राज्य पोषण कार्य योजना (2019-24)।

(4) http//www.prabhatkhabar.com

(5) http//www.livehindustan.com

(6) नीति आयोग बेबसाइट, भारत सरकार।